उत्तर प्रदेश बजट (2021-22) मुख्य बिंदु: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में होने वाले चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। इस साल बजट में प्रमुख आकर्षण में अयोध्या का विकास, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण, नए राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश बजट 2021 नोट्स UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 और अन्य आगामी परीक्षाओं जैसे कि UPPSC RO/ARO, उत्तर प्रदेश पुलिस, लोअर पीसीएस इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर प्रदेश के बजट (2021-22) हाइलाइट्स

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बजट पेश किया था। 2021-22 की बजट राशि **5,50,270.78 करोड़ रुपये** (विगत वर्ष के खर्च के आकार से 37,410 करोड़ रुपये अधिक) है जो इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है।

यह पहला पेपरलेस बजट है और वर्तमान सरकार का पांचवा बजट भी है।

उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के माध्यम से 23.36 लाख करोड़ रुपयों की वसूली की।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 202** के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा।
- संविधान में **"वार्षिक वित्तीय विवरण"** के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर "बजट" के रूप में जाना जाता है।

बजट में प्रयुक्त प्रमुख शब्द

<u>राजस्व में शामिल हैं:</u>

- **राजस्व प्राप्ति**
- **राजस्व व्यय**

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

राजस्व प्राप्ति:

- प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।
- इसमें सरकार द्वारा करों और गैर-कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से संकलित आय शामिल हैं।

राजस्व व्यय:

- ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए खर्च हैं।
- इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल हैं, राज्य सरकार को दिए गए अनुदान जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार शामिल हैं।
- इसमें विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

gradeup

पूंजीगत व्यय

- यह सरकार द्वारा किया गया खर्च है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है।
- इसमें भूमि, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होगा।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण (mortgages) और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल हैं।

<u>पूंजी जिसमें शामिल हैं</u>

- **पूंजीगत प्राप्ति**
- **पूंजीगत व्यय**

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

पूंजीगत प्राप्ति: वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं।

प्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो किसी व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। इसमें शामिल हैं-

- आयकर
- निगम कर

अप्रत्यक्ष कर: ये ऐसे कर हैं जो माल एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इसमें निम्न कर शामिल हैं

- सेवा कर
- आबकारी कर
- सीमा शुल्क

राजकोषीय नीति: राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है।

राजस्व घाटा: यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय है।

राजकोषीय घाटा: यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जिसमें उधार शामिल नहीं है।

प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है।

गैर-कर राजस्व: ये सरकारी राजस्व हैं जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य है।
- यह एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- FY22 के लिए राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- यह अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता GSDP का 28.1% है।
- FY21 बजट की तुलना में इसके अंतर्गत रुपये 37,410 करोड़ रूपये या 7.3% की वृद्धि हुई हैं

व्यय

- राजस्व व्यय के रूप में 3.95 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पूंजी खाता 1.55 लाख करोड़ रुपये है।

कुल प्राप्तियां

- कुल प्राप्तियों का अनुमान 5.06 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें शामिल हैं।
  - राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से 4.18 लाख करोड़ रुपये
  - पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 87,841.40 करोड़ रुपये
  - सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये
  - 1.19 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी।
  - लोक खता में प्राप्तियों से 5,500 करोड़ रुपये।

राजकोषीय घाटा

- वित्त वर्ष 22 के लिए राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता GSDP का 28.1% है।

राजस्व बचत

- यह 23,210.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

समेकित निधि

- राजस्व कटौती के बाद कुल घाटे में 44,088.94 करोड़ रुपये का अनुमान है।

बजट 2021-2022 में नई योजना / नीति

- **मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना योजना**

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करना है जो अन्य राज्यों से आए थे।
- तालाबंदी के दौरान लगभग 40 लाख अपने पैतृक जिलों में पहुंचाए गए।
- इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **मुख्यमंत्री मुद्रा योजना कल्याण योजना** के तहत 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ।

- **आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश**
  - यह योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के समकक्ष है।
  - इस योजना के तहत, राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर जोर देगी।

क्षेत्रवार व्यय

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

- **कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (2021-22 में):** बजट में किसानों की आय को दोगुना करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- किसानों को रियायती दरों पर आसान ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं।
- पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27,123 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से राज्य के किसानों को हस्तांतरित किए गए हैं।
- विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य घोषित किया गया है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 12,242 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- 39 जिलों के रूप में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 5,085 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
- विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 7,157 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं
  - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपये,
  - आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत योजना

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ और
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा

- 13 जिलों - बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, और कौशाम्बी में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1,950 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- पीपीपी मोड में चालू करने के लिए राज्य के 16 अनारक्षित जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत खर्च करने के लिए 23 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, और मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 960 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं।
- अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
- प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

परिवहन

- उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए 10,650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में तीन निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के लिए 3,450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  - 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़,
  - 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,107 करोड़ और
  - 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 870 करोड़,
- 594 किमी लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और इसके निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हवाई अड्डों के लिए 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।
- जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- अयोध्या में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये।
- अन्य आवंटन-
    - कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपये
    - रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 478 करोड़ रुपये और
    - दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS गलियारे के लिए 1,326 करोड़ रुपये।
    - वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।

पर्यटन

- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वाराणसी और अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर क्रमशः 100 खर्च किए जाएंगे।

संस्कृति

- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी विकास को

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 10,029 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत योजना (ग्रामीण) पर 2031 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 1400 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत योजना (ग्रामीण)
- AMRUT योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2,000 करोड़ रु।
- मुख्यमंत्री संपर्क योजना विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- पीएम आवास (ग्रामीण) के लिए 7,000 करोड़ रुपये और पीएम आवास योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये।
- जल मिशन (शहरी) को 2000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू किया जाएगा।

MSME क्षेत्र

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- एक जनपद- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- सरकार ने 2020-21 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का 5.5% आवंटित किया है, जो कि अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (5.3%) से अधिक है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 3,845 करोड़ रुपये आवंटित।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कुल 3,578 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
- हर जिले में पुलिस क्वार्टरों का नाम बदलकर महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पालनहार योजना के तहत 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये।
- सामाजिक वानिकी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।

श्रम

- मुख्यमंत्री प्रवासी कामधाम उधमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 12 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री मुद्रा योजना बीमा योजना पर खर्च किए जाएंगे।

युवा सशक्तिकरण

- छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021-22 से शुरू की गई है, साथ ही योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।
- युवा खेल विकास और प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- मेरठ में एक नया खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण

- महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।
- 100 करोड़ रुपये का आवंटन मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत किया गया है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम को 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण योजना को 415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पंचायती राज

- मुख्यमंत्री पंचायत प्रसार योजना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- डॉ। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस का प्रसार करने के लिए।
- 653 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

1. **उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कितनी बार बजट पेश किया है?**

उत्तर 5 बार

2. उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी?

उत्तर प्रयागराज

3. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए बजट आवंटन क्या है?

उत्तर 600 करोड़ रुपये

4. उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा होगा

उत्तर 90, 730 करोड़ रुपये

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

5. आत्मनिर्भर कृषक सम्मान योजना के लिए बजट आवंटन है?

उत्तर 100 करोड़ रूपये

gradeup

Gradeup UP State Exams Super Subscription | Access to all Structured Courses & Test Series ENROL NOW